

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2012

विषय:—जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उफल्डा के भवन निर्माण हेतु 0.255 है0 भूमि, विद्यालयी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्र सं0-879/11-25/(2011-12) दिनांक-02.04.2012, जो शासन को सम्बोधित तथा प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उफल्डा के भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता संख्या-15 मध्ये खेत संख्या-219 रकबा 0.845 है0 भूमि 12.11/16 नाली (0.255 है0) भूमि, जो उत्तराखण्ड सरकार के नाम श्रेणी-10(4) दर्ज अभिलेख है, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-2002 में निहित प्राविधानों एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9/

- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनागत शक्त से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

प्र०प०संख्या-866 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 5- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।